



RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 146

दि. 25.09.2025,

गुरुवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं में 91,770 करोड़ रुपये से अधिक की स्वच्छ ऊर्जा और पारेषण परियोजनाएं शामिल होंगी।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ा बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की 16,050 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली पीएम कुसुम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान से तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे राज्य और उत्तरी क्षेत्र के बीच संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरा पर रहेंगे। वे सुबह लगभग 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो-2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद, प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा करेंगे और 1,22,100 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद, दोपहर लगभग 1:45 बजे बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे पीएम कुसुम लाभाधिकारों से भी बातचीत करेंगे।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप,



प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो-2025 (यूपीआईटीएस-2025) का उद्घाटन करेंगे। यह व्यापार मेला, "परम स्रोत यहीं से शुरू होता है" विषय पर 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया

जाएगा। इसके तीन मुख्य उद्देश्य होंगे: नवाचार, एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण। एक त्रि-आयामी क्रेता रणनीति अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं, घरेलू व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) क्रेताओं और घरेलू व्यवसाय-से-उपभोक्ता (B2C) क्रेताओं को लक्षित करेगी, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं, सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे।

यूपीआईटीएस-2025 राज्य की विविध शिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, शसक्त एमएसएमई और उभरते उद्यमियों को एक ही मंच पर प्रदर्शित करेगा। इसमें हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयुष आदि प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी एक ही मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में भाग लिया



(जीएनएस)। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज (24 सितंबर, 2025) नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने संबोधन में सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनका काम अन्य कलाकारों को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा

में कला को लंबे समय से एक आध्यात्मिक साधना माना जाता रहा है। कला न केवल सौंदर्यबोध का माध्यम है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और एक अधिक संवेदनशील समाज के निर्माण का एक शसक्त माध्यम भी है। उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कलाकार अपने विचारों, दृष्टि और कल्पना के माध्यम से एक नए भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं।



राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि कलाकार कला सृजन के लिए अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगाते हैं। उनकी कलाकृतियों का उचित मूल्य कलाकारों और कला को पेशे के रूप में अपनाने के इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित करेगा। उन् होने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ललित कला अकादमी कलाकारों की कलाकृतियों की बिक्री को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि

भूमध्य सागर में तैनाती के

(जीएनएस)। भारतीय नौसेना की स्टील्थ फ्रिगेट पोत-आईएनएस त्रिकंद, भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के दौरान 21 सितंबर 2025 को साइप्रस के दक्षिणी तट पर स्थित लिमासोल पहुंचा।

वहां पहुंचने पर पोत के कर्मांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुलकर्णी ने साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त श्री मनीष और साइप्रस नौसेना के कमांडर, कमोडोर मिनास सोलोमोनोइडेस से मुलाकात की।

बंदरगाह पर प्रवास के दौरान पेशेवर संवाद, योग और जहाज पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान गतिविधियां आयोजित हुईं। 23 सितंबर 2025 को जहाज पर आगंतुकों का भी स्वागत किया गया।

तहत आईएनएस त्रिकंद साइप्रस के लिमासोल पहुंचा



भूमध्यसागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के पारस्परिक संकल्प को दर्शाती है।

टिकाऊ पशुपालन के लिए आयुर्वेद-समर्थित पशु चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है: श्री नरेश पाल गंगवार

(जीएनएस)। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने पशुपालकों के लिए एथनो वेटेनरी मेडिसिन (ईवीएम) पर एक वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। 23 सितंबर 2025 को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क के माध्यम से यह कार्यक्रम, 'जन-जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद' विषय के साथ संपन्न 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। डीएएचडी के सचिव श्री नरेश पाल गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 23 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 2,000 से अधिक सीएससी केंद्रों के पशुपालक एक साथ जुटे और एक लाख से

अधिक किसानों ने इसमें भाग लिया। श्री नरेश पाल गंगवार ने इस अवसर पर अपने संबोधन में टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद को आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत करने के महत्व पर बल दिया।



एटीबायोटेक प्रतिरोध की बढ़ती चुनौती पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल

विकल्प के रूप में एथनो वेटेनरी मेडिसिन (ईवीएम) की भूमिका को रेखांकित किया। श्री गंगवार ने पशु चिकित्सा सेवाओं तक किसानों की पहुंच को समझने और पशु रोगों के इलाज के लिए ईवीएम को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसानों के साथ बातचीत की। डीएएचडी की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी ने अपने संबोधन में 'बोवाइन मैस्टाइटिस' अर्थात् गोजातीय स्तनदाह के इलाज में ईवीएम के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सिंथेटिक एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता कम करके और प्राकृतिक, पारंपरिक उपचारों को बढ़ावा देकर रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एमआर) का मुकाबला करने में इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में स्वच्छता ही सेवा अभियान आरंभ

देश को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान



स्वच्छता ही सेवा' अभियान 2025 आयोजित कर रहा है। इस वर्ष स्वच्छोत्सव विषयवस्तु के अंतर्गत चलाया जा रहा यह अभियान 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस के रूप में संपन्न होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक

- राज्य में नई 17 तहसीलों के गठन को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी, कुल तहसीलों की संख्या अब 265 होगी
- नए वाव-थराद जिले के गठन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का एक और जनोन्मुखी निर्णय
- 2013 के बाद पहली बार जिला-तहसीलों की संख्या में बड़ा फेरबदल होगा
- प्रधानमंत्री ग्रामोत्थान योजना का लाभ मिलने से नवगठित होने वाले तहसील मुख्यालयों का शहरी तर्ज पर विकास हो सकेगा
- प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकसित भारत@2047 के संकल्प में विकसित गुजरात@2047 के लिए नई तहसीलों का गठन महत्वपूर्ण सिद्ध होगा

गांधीनगर, 24 सितंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने राज्य के अखिर विकास को गति देने वाला महत्वपूर्ण जन हितकार निर्णय किया है।

राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों, जनता के सभी वर्गों तथा पदाधिकारियों की भावनाओं तथा प्रस्तुतियों पर सकारात्मक प्रतिभाव देते हुए बनासकांठा जिले का विभाजन कर नए वाव-थराद जिले तथा राज्य की वर्तमान 21 तहसीलों का विभाजन

कर नई 21 तहसीलों के गठन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए

क्र.	जिला	पुरा तहसील/तहसीलों के नाम	नई प्रस्तावित तहसील का नाम	प्रस्तावित मुख्यालय
(1)	महिसागर/पंचमहाल	बालासमुद्र तथा रावेले	मोहर	मोहर
(2)		लुणावाडा	केडेवा	केडेवा
(3)		इंदिरावाडा	चिकेवा	चिकेवा
(4)		कलसाडा	नया चोडा	नया चोडा
(5)	बनासकांठा	वावी जयन्, कपराडा, पाटडी	राह	राह
(6)		बाद	धरापीड	दीना
(7)		कांकेरव	ओगाड	बाद
(8)		दीठा	इडाद	इडाद
(9)	छावोड	झालोड	गोविंद पुर लोन्डी	लोन्डी
(10)		फोडो	मुछार	मुछार
(11)		केलूप पावी	कटवाल	कटवाल
(12)		कडवनेव तथा कडताल	धरासेल	कादडीस (पिछाडी)
(13)	अनूपल्ली	मिठाडा	शामवासी	शामवासी
(14)		बागड	साठवा	साठवा
(15)		सोनाड	उकई	उकई
(16)		माडवी	ओड	ओड
(17)	सुप	मुडवा	ओडवा	कलवाडा

बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रशासनिक सरलीकरण का जो विचार दिया है, उसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में वर्तमान राज्य सरकार वेगवान बना रही है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में शासन में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण से जिला-तहसील स्तरीय कार्यालयों के साथ कामकाज में सुगमता आए तथा नया तहसील मुख्यालय नजदीक में प्राप्त होने से सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सहित सर्वग्राही सुविधाओं में वृद्धि हो और सुदूरवर्ती गांवों से तहसील मुख्यालय पर आने-जाने में समय, शक्ति तथा धन की बचत हो; ऐसे जन हितकारी उदार दृष्टिकोण से इन नई 17 तहसीलों के गठन को

मंजूरी दी है। प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि वाव-थराद जिले में वर्तमान बनासकांठा जिले की 6 तहसीलों वाव, थराद, सुईगाम, भाभर, दियोदर तथा लाखणी

क्र.	जिला	पुरा तहसील/तहसीलों के नाम	नई प्रस्तावित तहसील का नाम	प्रस्तावित मुख्यालय
(1)	महिसागर/पंचमहाल	बालासमुद्र तथा रावेले	मोहर	मोहर
(2)		लुणावाडा	केडेवा	केडेवा
(3)		इंदिरावाडा	चिकेवा	चिकेवा
(4)		कलसाडा	नया चोडा	नया चोडा
(5)	बनासकांठा	वावी जयन्, कपराडा, पाटडी	राह	राह
(6)		बाद	धरापीड	दीना
(7)		कांकेरव	ओगाड	बाद
(8)		दीठा	इडाद	इडाद
(9)	छावोड	झालोड	गोविंद पुर लोन्डी	लोन्डी
(10)		फोडो	मुछार	मुछार
(11)		केलूप पावी	कटवाल	कटवाल
(12)		कडवनेव तथा कडताल	धरासेल	कादडीस (पिछाडी)
(13)	अनूपल्ली	मिठाडा	शामवासी	शामवासी
(14)		बागड	साठवा	साठवा
(15)		सोनाड	उकई	उकई
(16)		माडवी	ओड	ओड
(17)	सुप	मुडवा	ओडवा	कलवाडा

का समावेश कर थराद को जिला मुख्यालय बनाते हुए वाव-थराद जिले के गठन को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है।

उन्होंने नई तहसीलों के गठन का विवरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में तहसील इकाई को विकास एवं प्रशासन में अधिक शसक्त बनाने के लिए आपणो तालुको-वाइब्रेट तालुको (एटीवीटी) की विभाजना दी थी और 2013 में नई 23 तहसीलों के गठन की घोषणा की थी। उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने सर्वाधिक 17 नई तहसीलों के गठन का निर्णय किया है।

श्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि

1.36 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को कौशल उन्नयन और भविष्य के लिए तैयार होने हेतु आईजीओटी पोर्टल पर नामांकित किया गया: डॉ. सिंह

कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री ने प्रशासन और प्रशिक्षण में 'संपूर्ण सरकार' मॉडल के लिए 'केन्द्र-राज्य एकीकरण का आ'न किया विज्ञान प्रशासकों के लिए सप्ताह भर के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई गई विकसित भारत 2047 के लिए बेवसाकं विज्ञन के लिए डीएआरपीजी सेल (जीएनएस)।

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक

शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सेवाओं को लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और एआई-संचालित उपकरण मिशन कर्मयोगी 2.0 के केंद्र में होंगे, जिससे विभाग-स्तरीय और राज्य-स्तरीय क्षमता निर्माण योजनाओं (सीबीपी) का निर्माण संभव होगा।



आई गौट कर्मयोगी पोर्टल पर नामांकन कराया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो क्षमता निर्माण के प्राथमिक केंद्रों के रूप में एटीआई को समर्थन और मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और एआई-संचालित उपकरण मिशन कर्मयोगी 2.0 के केंद्र में होंगे, जिससे विभाग-स्तरीय और राज्य-स्तरीय क्षमता निर्माण योजनाओं (सीबीपी) का निर्माण संभव होगा।



गरवी गुजरात हिन्दी



JioTV CHENNAL NO. 2002



Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

सम्पादकीय

सीतापुर जेल से रिहाई पाकर भी सपा के वरिष्ठ नेता आजम की मुश्किलें नहीं आसान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व वैबिनेट मंत्री आजम खां की 23 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहाई तो हो गई लेकिन सवाला यह है कि 104 मुकदमों में से मात्र 12 मामलों का ही पैसला हुआ है जिनमें वे 7 में अपराध मुक्त हुए हैं जबकि 5 में उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे में उनकी आजादी कितने दिनों तक रह सकेगी।

दरअसल आजम खां पर अभी भी 80 से अधिक मुकदमों उनके खिलाफ विचाराधीन हैं जिनमें 59 मजिस्ट्रेट कोर्ट, 19 सेशन कोर्ट और तीन जिला अदालतों में लंबित हैं। ड्रॉपर प्रकरण और जन्म प्रमाण पत्र जालसाजी के मामले बहुत गंभीर हैं जिनमें उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा हो चुकी है। बाकी मामलों में या तो वे बरी हो गए या फिर जमानत पर हैं। आजम खां पर भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 471 और 201 जैसी गंभीर आपराधिक धाराएं लगी हैं। ऐसा नहीं है कि अपने खिलाफ लगे आरोपों के खिलाफ आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुहार नहीं लगाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार से लेकर सांप्रदायिक विद्वेष तक का आरोप लगाया किन्तु कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसलिए उन्हें जेल और अदालतों में ही समय बिताना पड़ रहा है। कहीं किसी एक मामले में उन्हें राहत मिल भी जाती है तो दूसरे मामले तैयार हो जाते हैं। अब भी नए मामले निकल रहे हैं जिनके लिए रामपुर पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया है।

मतलब यह कि आजम खां खुद तो मुकदमों के जाल में फंसे हैं जबकि अखिलेश यादव उन्हें आशवासन दे रहे हैं कि यदि सपा की राज्य में सरकार बनी तो उनके खिलाफ जितने भी मुकदमें दर्ज हैं सारे वापस ले लिए जाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि आजम खां पर सारे मामले उन्हीं दिनों के हैं जब वे मुलायम सिंह एवं अखिलेश यादव के शासन काल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा गंभीर प्रवृति का नहीं है जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में रही हो। इसका मतलब है कि आजम खां ने सत्ता का दुरुपयोग अपने आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया। इसमें उनकी मुलायम और अखिलेश का भी सहयोग मिला।

बहरहाल यह तथ्य तो सार्वजनिक है कि अभी आजम खां की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए अखिलेश मुस्लिम समाज की सहानुभूति हासिल करने के उद्देश्य से भी आजम के खिलाफ मुकदमों खत्म करने की बात कर रहे हैं। यह सच है कि आजम खां ने जिन्दी उम्मीद अखिलेश और समाजवादी पार्टी से की थी उतनी मदद न तो पार्टी से मिली और न ही यादव परिवार से। आजम खां और उनकी पत्नी तथा पुत्र सभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते किन्तु जब वे जेल गए तो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्य, जिला या पुलिस स्टेशन स्तर का धरना प्रदर्शन करने की जरूरत भी नहीं समझी। यही कारण है कि आजम खां और उनका परिवार बहुत ज्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी और अखिलेश से नहीं करता। यही कारण है कि कुछ लाल बुझकड़ पत्रकार अनुमान लगा रहे हैं कि आजम खां समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन यह आंकलन सही इसलिए नहीं लगता कि आजम को अपनी औकात पता है। राज्य के मुस्लिम समाज के लोगों को यदि अखिलेश और आजम खां के बीच में से एक को चुनना हो तो वे आजम को नहीं बल्कि अखिलेश को चुनेंगे। कारण है कि आजम खां ने मुसलमानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है जबकि अखिलेश ने वोट के लिए मुसलमानों के हित के लिए राज्य के संसाधन का इस्तेमाल किया। लम्बोलुआब यह है कि समाजवादी पार्टी आजम खां का नाम लेकर मुस्लिम समाज में अपनी छवि चमकाने का काम करती रहेगी किन्तु अपने मुकदमों का सामना तो आजम खां को खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि अब अदालतों ने सरकारों के कहने पर आपराधिक मामलों को वापस लेना बन्द कर दिया है या फिर बहुत कम कर दिया है।

प्रधानमंत्री 25 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लेंगे

पीएमएफएमई योजना के तहत, **खाद्य प्रसंस्करण** क्षेत्र में सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 **लाभार्थियों** को 770 **करोड़ रुपये** से अधिक की ऋण-आधारित सहायता प्रदान की जाएगी (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को शाम लगभग 6:15 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे।

25 से 28 सितंबर तक वर्ल्ड फूड

इंडिया 2025 आयोजित किया जाएगा और इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य के क्षेत्र में स्थायित्व और पौष्टिक एवं जैविक खाद्य के उत्पादन में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा।

वर्ल्ड फूड इंडिया में, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2,510 करोड़ रुपये से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण-आधारित सहायता प्रदान की जाएगी।

वर्ल्ड फूड इंडिया में सीईओ

उद्योग क्षेत्र में नारीशक्ति : महिला उद्यमी शिल्पा मलिक सफलतापूर्वक कर रही हैं टेक इनोवेशन आधारित स्टार्टअप



'बायोस्कैन रिसर्च' का नेतृत्व बायोस्कैन रिसर्च बनाता है ब्रेन इंजरी की तत्काल जाँच करने वाले नॉन-इन्वेसिव, पोर्टेबल **ऑनसाइट डिटेक्शन टूल्स** स्टार्टअप ने अब तक 70 यूनिट्स की बिक्री की है, सर्वाधिक बिक्री राज्य सरकार के प्राइमरी व कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों तथा **ट्रॉमा सेंटरों** में गांधीनगर, (जीएनएस)। 24 सितंबर :समग्र गुजरात इस समय

विश्व का सबसे लंबा नृत्य पर्व नवरात्रि मना रहा है। नवरात्रि का पर्व नारीशक्ति के उत्सव तथा महिलाओं की सक्षमता को उजागर करने का पर्व है। महिलाएँ आज सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रही हैं; फिर वह शिक्षा क्षेत्र हो, खेल-कूद क्षेत्र हो या उद्योग जगत। समग्र विश्व में आज जब महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और महिलाओं के नेतृत्व में सफल औद्योगिक इकाइयाँ तथा स्टार्टअप्स के अनेक उदाहरण हैं, तब गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। आज गुजरात की ऐसी ही एक महिला उद्यमी शिल्पा मलिक तथा उनके स्टार्टअप 'बायोस्कैन रिसर्च' के विषय में बात करनी है। उनके नेतृत्व में बायोस्कैन रिसर्च आज गुजरात के एक सफल स्टार्टअप के रूप में कार्यरत है, जो जानलेवा रोगों का प्रारंभिक निदान करने वाले चिकित्सा उपकरण बनाकर

है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री मोदी ने मिशन मंगलम योजना, वुमन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष महिला औद्योगिक पार्क (वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पार्क), महिला आर्थिक विकास निगम आदि की स्थापना की। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल श्री मोदी की इन महिला केन्द्रित योजनाओं को आगे बढ़ाकर वुमन लेड डेवलपमेंट के उनके विजन को चरितार्थ कर रहे हैं।

बायोस्कैन रिसर्च बनाता है जानलेवा रोगों का प्रारंभिक निदान करने वाले चिकित्सा उपकरण बायोस्कैन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना सितंबर-2017 में सह-संस्थापकों (को-फाउंडर्स) शिल्पा मलिक तथा अनुपम लवाणिya द्वारा अहमदाबाद में की गई थी। शिल्पा मलिक बायोस्कैन रिसर्च की को-फाउंडर तथा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। वे हार्डवेयर इनोवेशन में एक दशक का अनुभव रखने वाली एक सफल टेक्नोप्रेन्योर हैं। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वैज्ञानिक के रूप में सेवा दी है तथा मिनिटरी सेंसर सिस्टम डिजाइन व मैनेजमेंट पर कार्य किया है।

शिल्पा मलिक के नेतृत्व में बायोस्कैन रिसर्च ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जैसी जानलेवा बीमारी का अनाक्रामक रूप से (नॉन-इन्वेसिवली) प्रारंभिक

*

सत्र भी होंगे जिनमें भारत एक वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्थायित्व और नेट जीरो, खाद्य प्रसंस्करण में अग्रणी, भारत का पाकेत पशु आधारित खाद्य उद्योग, पोषण और स्वास्थ्य के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पादप-आधारित खाद्य पदार्थ, न्यूट्रस्युटिकल्स, विशिष्ट खाद्य पदार्थ आदि जैसे विविध विषयों पर चर्चा होगी। इसमें 14 मंडप होंगे, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट विषयों को समर्पित होगा। कार्यक्रम में लगभग 1,00,000 आगंतुक शामिल होंगे।

ढांचे में लागत-प्रभावी रहते हुए स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के संतुलित क्षेत्रीय वितरण को बढ़ाना है। दीर्घावधि में, ये योजनाएं वर्तमान और उभरती स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए देश की समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाएंगी।

रोजगार सृजन सहित प्रभाव: योजनाओं के अपेक्षित प्रमुख प्रभाव/परिणाम निम्नलिखित हैं: भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करना।

वैश्विक मानकों के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण गुणवत्ता बढ़ाना।

डॉक्टरों और विशेषज्ञों की पर्याप्त उपलब्धता भारत को सस्ती दर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रमुख र्थ स्थान के रूप में स्थापित कर सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन भी बढ़ेगा।

स्वास्थ्य सेवा पहुंच में विशेष

अनेक लोगों का जीवन बचा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सदैव प्राथमिकता दी



उचित दरों पर उनकी बिक्री करता है। इस समग्र प्रक्रिया के लिए वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स तथा सॉफ्टवेयर में डीपटेक का उपयोग करते हैं। बायोस्कैन रिसर्च ने इंटरक्रैनियल रक्तस्राव, सरल शब्दों में ब्रेन इंजरी की पहले से जाँच के लिए नॉन-इन्वेसिव, पोर्टेबल ऑनसाइट डिटेक्शन टूल्स विकसित किए हैं, जिससे समय रहते निदान कर लोगों का जीवन बचाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि बायोस्कैन रिसर्च ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी (आई-क्रिएट), जो टेक इनोवेशन पर आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने वाला गुजरात सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है, उससे सहायता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी)-कानपुर, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल (बीआईआरएसी), डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च (बीएचआर) तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) से भी इस स्टार्टअप को वित्तीय

साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को 4-लेन का बनाने के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर मिली मंजूरी

कैबिनेट ने बिहार में 3,822.31 करोड़ रुपए की लागत से एनएच-139डब्ल्यू के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को 4-लेन का बनाने के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज बिहार में एनएच-139डब्ल्यू के साहेबगंज-भारत का पाकेत पशु आधारित खाद्य उद्योग, पोषण और स्वास्थ्य के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पादप-आधारित खाद्य पदार्थ, न्यूट्रस्युटिकल्स, विशिष्ट खाद्य पदार्थ आदि जैसे विविध विषयों पर चर्चा होगी। इसमें 14 मंडप होंगे, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट विषयों को समर्पित होगा। कार्यक्रम में लगभग 1,00,000 आगंतुक शामिल होंगे।

इस प्रस्तावित चार-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्देश्य राज्य की राजधानी पटना और बेतिया के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। इससे उत्तर बिहार के वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले, भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों तक जुड़ जाएंगे। यह परियोजना लंबी दूरी के माल परिवहन को बढ़ावा देगी, प्रमुख बुनियादी ढांचे तक पहुंच में

सहयोग प्राप्त हुआ है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 1500 रोगियों पर परीक्षण, 11 हजार से अधिक ब्रेन स्कैन



बायोस्कैन रिसर्च प्रा. लि. की जर्नी की चर्चा करते हुए उसकी को-फाउंडर शिल्पा मलिक कहती हैं, 'हमारे परिवार के सदस्य का ब्रेन इंजरी हुई थी और उसके उपचार के दौरान हमें जानने को मिला कि समस्या ब्रेन इंजरी की नहीं है, बल्कि अलीं डिटेक्शन यानी शीघ्र निदान की है और अनेक रोगी शीघ्र निदान न हो पाने के कारण पीड़ा सहन करते हैं। हमारा बैकग्राउंड तो टेक्निनकल था ही। इसलिए हमने अलीं डिटेक्शन के लिए मेडिकल डिवाइस विकसित करने के लिए स्टार्टअप शुरू करने का निश्चय किया। हमने 4-5 वर्ष रिसर्च में लगाए और सितंबर 2017 में बायोस्कैन रिसर्च की स्थापना की।'

ब्रेन इंजरी का निदान करने वाला मेडिकल डिवाइस बनाने के बाद उसका पेटेंट फाइल करने के लिए भी उन्हें गुजरात सरकार का सहयोग मिला। उन्होंने 3 वर्ष क्लिनिकल रिसर्च के लिए लगाए। इस दौरान उन्होंने अपने बनाए डिवाइस का रोगियों पर परीक्षण किया। गुजरात में परीक्षाओं के बाद समग्र भारत के

विभिन्न अस्पतालों में उनके बनाए ब्रेन इंजरी के अलीं डिटेक्शन के चिकित्सा उपकरणों का परीक्षण किया गया। इनमें एनआईएमएचएएनएस-बेंगलुरु



तथा एम्स-भोपास जैसे देश के अग्रणी अस्पतालों के न्युरोसर्जन भी शामिल हुए। 2 वर्ष की क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 1500 रोगियों पर परीक्षण किया गया है और 11,000 ब्रेन स्कैन किए गए। सफल परीक्षाओं के बाद उन्होंने इस डिवाइस को बिक्री के लिए लॉन्च किया।

ऑल ओवर इंडिया में लगभग 70 यूनिट्स की बिक्री, सर्वाधिक बिक्री सरकारी प्राथमिक-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

शिल्पा मलिक ने बताया कि अब तक ऑल ओवर इंडिया में वे अपने उत्पाद के लगभग 70 यूनिट्स की बिक्री कर चुके हैं। उनके द्वारा विकसित किए गए डिवाइस की परफॉर्मेंस एक्यूरेसी 95 प्रतिशत तथा सेंसेटिविटी 97 प्रतिशत है। वे कहती हैं, 'इस मेडिकल डिवाइस के लिए सरकारी विभाग से हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिला है और हम सर्वाधिक डिवाइस की बिक्री भी सरकार को ही यानी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ट्रॉमा सेंटरों में करते हैं।' उनके डिवाइस की हाई एक्यूरेसी को देखते हुए डॉक्टर्स भी उन पर भरोसा जताते हैं।

(साहेबगंज), सोमेश्वरनाथ मंदिर (अरेराज), जैन मंदिर और विश्व शांति स्तूप (वैशाली) और महावीर मंदिर (पटना) सहित प्रमुख विरासत



यह परियोजना सात पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, छह सामाजिक नोड्स, आठ लॉजिस्टिक नोड्स, नौ प्रमुख पर्यटन और धार्मिक केंद्रों को मजबूती मिलेगी। एनएच-139डब्ल्यू की योजना

बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किलोमीटर) के दोहरीकरण को भी मिली स्वीकृति

कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किलोमीटर) के दोहरीकरण को स्वीकृति दी, जिसकी कुल लागत **2,192 करोड़ रुपये** है (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान की, जिसकी कुल लागत लगभग 2,192 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना बिहार राज्य के चार जिलों को कवर करेगी और

भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 104 किलोमीटर की वृद्धि रहेगी।

यह रेल मार्ग राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, जो देश भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

इस मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 1,434 गांवों और लगभग 13.46 लाख आबादी, जिसमें दो आकांक्षी जिलें (गया और नवादा) शामिल हैं, की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

ये मार्ग कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, फ्लाई ऐश आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्क है। क्षमता वृद्धि

टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन साधन होने के नाते देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और रसद लागत को कम करने में मदद करेगा, साथ ही तेल आयात (5 करोड़ लीटर) को घटाएगा और सीओ2 उत्सर्जन (24 करोड़ किलोग्राम) को कम करेगा, जो एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा तथा भारतीय रेल की कार्यकुशलता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी-ट्रैकिंग का यह प्रस्ताव परिचालन को सुगम बनाएगा और भीड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे की

बायोस्कैन रिसर्च को मिले हैं 50 से अधिक अर्वाइर्स शिल्पा मलिक के सफल नेतृत्व में बायोस्कैन रिसर्च को कई प्रतिष्ठित



अर्वाइर्स/मान्यताएँ मिले हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण अर्वाइर्स निम्नानुसार हैं :

● इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा बेस्ट एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च अर्वाइ (2024)

● इंडिया इजराइल इनोवेशन चैलेंज के विजेता के रूप में सम्मान

● अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (एएसएमई) द्वारा बेस्ट हेल्थकेयर इनोवेशन ऑफ इंडिया अर्वाइ

● हाल ही में, जीआईएस्टेक्स (जीटैक्स) थाईलैंड द्वारा सुपरनोवा विजेता (बेस्ट डिजी हेल्थ एंड बायोटेक इनोवेशन ऑफ इंडिया)

● यूनिटस सीड फंड स्टारहेल्थ 2017 अंतर्गत बेस्ट हेल्थकेयर स्टार्टअप ऑफ इंडिया

● एआईसीटीई कनाडा इंडिया एक्सीलरेशन प्रोग्राम द्वारा भारत के चोटी के 10 वुमन लेड टेक स्टार्टअप्स में स्थान

● टीआईई-बीआईआरएसी डब्ल्यूआईएनईआर द्वारा भारत के चोटी के 15 वुमन लेड बायोटेक स्टार्टअप में स्थान

● इनफोसिस स्टार्टअप-

वैकल्पिक मार्गों को उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह एनएच-31, एनएच-722, एनएच-727, एनएच- 27 और एनएच-227ए के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में काम करेगा।

यह 100 किमी/घंटा की डिजाइन गति के लिए बनाया गया है लेकिन वाहनों के लिए 80 किमी/घंटा की औसत गति से चलने की क्षमता रखता है। इससे साहेबगंज और बेतिया के बीच कुल यात्रा समय, मौजूदा विकल्पों की तुलना में 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटा रह जाएगा। साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

78.94 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित परियोजना से लगभग 14.22 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और 17.69 लाख मानव दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और इस परियोजना से अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'नए भारत' के विजन के अनुरूप हैं, जो इस क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से "आत्मनिर्भर" बनाएंगी, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने पर केन्द्रीत है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

ब्लॉक के कारण 25 सितम्बर की पोरबंदर-मुजप्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी

राजकोट, 24 सितम्बर, 2025
पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर क्षेत्र में रेल संपर्क को और सुदृढ़ बनाने, गोरखपुर-डोमिनगढ़ के बीच 4 किमी नई तृतीय लाइन और गोरखपुर-नखहा जंगल के बीच 5 किमी का दोहरीकरण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के चलते राजकोट मंडल से होकर जानेवाली

साबरमती लोको शेड द्वारा WAG-9HC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पहला इंटरमीडिएट ओवरहॉल (IOH) सफलतापूर्वक संपन्न

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के साबरमती लोको शेड ने अपनी उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाते हुए उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हअक्क-9ल्टउ का पहला इंटरमीडिएट ओवरहॉल (कड्ल) सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह उपलब्धि लोको नं. 32322 पर हासिल की गई, जिसने शेड की तकनीकी दक्षता और समर्पण को और सशक्त रूप से स्थापित किया है।

साबरमती शेड की स्थापना वर्ष 1978 में टक्कू डीजल ज्ट4 लोकोमोटिव के रखरखाव हेतु की गई थी। वर्ष 2009 से शेड ने उच्च हॉर्स-पावर हउक्क डीजल लोकोमोटिव का रखरखाव प्रारंभ किया और निरंतर अपनी क्षमताओं का विस्तार करता

पश्चिम रेलवे द्वारा गांधीधाम-सियालदह स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांधीधाम-सियालदह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों को विस्तारित किया गया है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

पश्चिम रेलवे द्वारा छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

मुंबई, 24 सितंबर, 2025
पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष तौर पर त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 06 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09061/09062 बांद्रा टर्मिनस – बरौनी (साप्ताहिक) स्पेशल
ट्रेन संख्या 09061 बांद्रा टर्मिनस

25 सितम्बर को पोरबंदर-शालीमार सुपरफास्ट अहमदाबाद से चलेगी

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भावनगर मंडल के पोरबंदर स्टेशन से चलने वाली ट्रेन संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 25.09.2025 (गुरुवार) को पोरबंदर की बजाय अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन से प्रस्थान करेगी। अहमदाबाद जं. स्टेशन से प्रस्थान का समय 17.40 बजे रहेगा।

इस प्रकार यह ट्रेन पोरबंदर और

आईसीएआर ने स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान के तहत स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियां शुरू कीं 21 से 23 सितंबर तक 'स्वच्छोत्सव' मनाया

(जीएनएस)।
मौजूदा स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान 2025 और वर्ष के व्यापक विषय "स्वच्छोत्सव" के हिस्से के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और इसके संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के नेटवर्क ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 21 से 23 सितंबर 2025 तक कई केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया।

21 सितंबर को, सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए सफाई-मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें निवारक स्वास्थ्य जांच और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव को सुगम बनाना शामिल था, जो इन महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने को लेकर आईसीएआर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

22 सितंबर को, आईसीएआर के

25 सितम्बर, 2025 की ट्रेन नंबर 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

25 सितम्बर, 2025 को पोरबंदर से चलने वाली ट्रेन नंबर 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी –गोंडा-गोरखपुर-पनियहवा-नरकटियागंज-

रहा। मार्च 2023 में शेड को श्री-फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान कर्मचारियों ने वड़ोदरा, वटवा तथा

वलसाड इलेक्ट्रिक शेड से प्रशिक्षण प्राप्त कर अल्प समय में आवश्यक कौशल अर्जित किया। तत्पश्चात, अप्रैल 2025 से शेड ने सबसे शक्तिशाली हअक्क23 लोकोमोटिव का रखरखाव शुरू किया।

ट्रेन संख्या 09437 गांधीधाम-सियालदह स्पेशल जिसे 08 अक्टूबर 2025 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब 12 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09438 सियालदह-गांधीधाम स्पेशल जिसे

मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी-औंड़ि हार-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी।

इस मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन गोंडा, गोरखपुर, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सांगली, बापूधाम मोतिहारी और

चकिया स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।

केवल डेढ़ वर्ष के भीतर ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रखरखाव का अनुभव प्राप्त करते हुए शेड ने कड्ल कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार

केवल डेढ़ वर्ष के भीतर ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रखरखाव का अनुभव प्राप्त करते हुए शेड ने कड्ल कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार

सफलतापूर्वक संपन्न किया। उल्लेखनीय है कि कड्ल शेड्यूल हर छह वर्षों में किया जाता है, जिसमें लोकोमोटिव की सभी प्रणालियों का व्यापक निरीक्षण और ओवरहॉल शामिल होता है, ताकि अगले छह वर्षों

11 अक्टूबर 2025 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब 15 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09437 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 26 सितम्बर, 2025 से सभी पीआरएस कार्डटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर

ट्रेन संख्या 09041 उधना-बलिया स्पेशल को 27 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09042 बलिया-उधना स्पेशल को 28 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09067/09068 उधना-जयनगर (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन संख्या 09067 उधना-जयनगर स्पेशल को 23 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09068 जयनगर-उधना स्पेशल को 24 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09069/09070

अहमदाबाद से चलेगी

चलने वाली ट्रेन संख्या 12905 को पोरबंदर के स्थान पर अहमदाबाद से चलाया जाए।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

कोटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी), रसायन एवं उर्वरक हतिर भारत के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को दर्शायां। आईसीएआर के 113 अनुसंधान संस्थानों, 731 कृषि विज्ञान केंद्रों और देश भर के अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यान्वित इन गतिविधियों ने किसानों,

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। उपरोक्त ट्रेन के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

तक निर्बाध एवं विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी को अपने कौशल में निरंतर वृद्धि कर भारतीय रेल की सेवाओं को विश्वस्तरीय स्तर तक

पहुंचाने हेतु प्रेरित किया। यह उपलब्धि न केवल साबरमती शेड की तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि भारतीय रेल की निरंतर प्रगति और यात्रियों व ग्रहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

उधना-समस्तीपुर (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन संख्या 09069 उधना-समस्तीपुर स्पेशल को 23 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल को 25 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09437/09438 गांधीधाम-सियालदह (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन संख्या 09437 गांधीधाम-सियालदह स्पेशल को 12 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09438 सियालदह-गांधीधाम स्पेशल को 15 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09437 गांधीधाम-सियालदह स्पेशल को 12 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09438 सियालदह-गांधीधाम स्पेशल को 15 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09061, 09033, 09041, 09067, 09069 एवं 09437 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 26 सितम्बर, 2025 से सभी पीआरएस कार्डटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, जो ग्रामीण और शहरी भारत में दीर्घकालिक सतत विकास में योगदान देगी। ये गतिविधियां एक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर की अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं।

उद्घाटन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं प्रशिक्षण मैनुअल के विमोचन के साथ हुई। इस सत्र में डीसीपीसी के संयुक्त सचिव (पेट्रोकेमिकल्स) श्री दीपक मिश्रा, ओपीसीडब्ल्यू के प्रतिनिधि श्री मार्टिन ग्रांडे और आईपीएफटी के निदेशक डॉ. मोहना कृष्ण रेड्डी मुडियम के साथ-साथ कई प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

अहमदाबाद रेल मंडल में कवच प्रणाली का तेजी से विस्तार

अहमदाबाद मंडल में ट्रेन सुरक्षा के लिए 'कवच 4.0' इंस्टालेशन का कार्य जारी

अहमदाबाद-पालनपुर, सामाख्याली एवं गांधीधाम रेल मार्गों पर कवच इंस्टालेशन कार्य प्रगति पर
अहमदाबाद – गैरतपुर सेक्शन पर कवच इंस्टालेशन पूर्ण

कवच 4.0 एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। कवच एक उच्च प्रौद्योगिकी युक्त प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम क्रम (एसआइएल-4) के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच लोको पायलट को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में सहायता करता है, लोको पायलट के ऐसा करने में विफल रहने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर और

रखबा मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है। यह भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कम समय में भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित, परीक्षण और तैनात करना शुरू कर

कवच लोको शेड में कुल 169 इंजनों पर 'कवच' प्रणाली स्थापित करने की योजना है। अब तक 23 इंजनों पर यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष 146 इंजनों पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए 14 प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की एक समर्पित टीम नियुक्त की गई है, जो

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर क्षेत्र में रेल संपर्क को और सुदृढ़ बनाने, गोरखपुर-डोमिनगढ़ के बीच 4 किमी नई तृतीय लाइन और गोरखपुर-नखहा जंगल के बीच 5 किमी का दोहरीकरण कार्य के चलते भावनगर मंडल के पोरबंदर स्टेशन से 25 सितम्बर, 2025 से सभी पीआरएस कार्डटरों

25 सितम्बर, 2025 (गुरुवार) की ट्रेन नंबर 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी जं.-गोंडा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को स्वीकृति दी

(जीएनएस)।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10 लाख 91 हजार 146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के रूप में 1865 करोड़ 68 लाख रुपये के भुगतान को रू वीकृति दी। रेलवे कर्मचारियों के बेहतर कामकाज को मान् यता देते हुए यह मंजूरी दी गई है।

जहाज निर्माण, समुद्री क्षेत्र में वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को मजबूत करने के लिए व्यापक चहुंमुखी पहल

मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को कुल 24,736 करोड़ रुपये की राशि के साथ 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया गया

20,000 करोड़ रुपये के समुद्री क्षेत्र निवेश कोष के साथ समुद्री विकास निधि को मंजूरी दी गई

19,989 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जहाज निर्माण विकास योजना का लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन सकल टन भार तक विस्तारित करना है

(जीएनएस)।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के जहाज निर्माण और समुद्री इको-सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के एक व्यापक

एएसडीसी कार्यक्रम 14 देशों के 16 प्रतिभागियों को एक साथ लाया है, जिनमें ओपीसीडब्ल्यू देश जैसे बुरुंडी, केन्या, युगांडा, तंजानिया, फिलीपींस, मलेेशिया, श्रीलंका, जांबिया, लेसोथो, मोरक्को, ओमान, ब्राजील, मलावी और बारबाडोस के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हैं, विशेष रूप से विकासशील एवं बदलती अर्थव्यवस्थाओं से। इसका उद्देश्य तकनीकी क्षमता का निर्माण करना, संस्थापत विशेषज्ञता को बढ़ावा देना

दिया है।

'कवच' दो स्तरों पर कार्य करता है—एक उपकरण इंजन में लगाया जाता है जिसे लोको TCAS (Train Collision Avoidance System) कहा जाता है और दूसरा स्टेशन व रेल पटरियों पर स्थापित होता है जिसे स्टेशन TCAS कहा जाता है।

अहमदाबाद मंडल में 'कवच' प्रणाली का क्रियान्वयन

भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विकसित की गई उन्नत स्वदेशी प्रणाली 'कवच' का क्रियान्वयन अहमदाबाद मंडल में भी तीव्र गति से किया जा रहा है। यह प्रणाली ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित, उत्तरदायी तथा नियंत्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1. वटवा लोको शेड में कवच कार्य की प्रगति

वटवा लोको शेड में कुल 169 इंजनों पर 'कवच' प्रणाली स्थापित करने की योजना है। अब तक 23 इंजनों पर यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष 146 इंजनों पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए 14 प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की एक समर्पित टीम नियुक्त की गई है, जो

एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

25 सितम्बर, 2025 (गुरुवार) की ट्रेन नंबर 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी जं.-गोंडा

प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान किया जाता है। इस वर्ष भी, लगभग 10 लाख 91 हजार आवागमनत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है। रेलवे के समग्र प्रदर्शन में सुधार हेतु रेल कर्मचारियों को प्रेरित

प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान किया जाता है। इस वर्ष भी, लगभग 10 लाख 91 हजार आवागमनत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है। रेलवे के समग्र प्रदर्शन में सुधार हेतु रेल कर्मचारियों को प्रेरित

इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) को मंजूरी दी गई है। इसमें भारत सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी वाला 20,000 करोड़ रुपये का समुद्री निवेश कोष और ऋण की प्रभावी लागत कम करने तथा परियोजना की बैंकिंग क्षमता में सुधार हेतु 5,000 करोड़ रुपये का व्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इसके अलावा, 19,989 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) का उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन भार तक बढ़ाना, मेगा जहाज निर्माण समूहों को सहायता प्रदान करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना और जहाज रसायन परियोजनाओं के लिए बीमा सहायता

पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार करने, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ एक मजबूत समुद्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए चहुंमुखी पहल को प्रस्तुत करता है।

इस पैकेज के तहत, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएस) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा और इसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपये होगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा।

एवं रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के प्रभावी कार्यान्वयन में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। एएसडीसी के व्यापक प्रशिक्षण श्रृंखला में विषयों की एक विस्तृत यादी को कवर करते हैं, जिनमें शामिल हैं: अनुसूचित रसायनों की रासायनिक प्रतिक्रिया, अपघटन एवं परिशोधन। उन्नत गैस क्रोमैटोग्राफी एवं मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक। नमूना तैयारी एवं व्युत्पन्नकरण विधियां।

अच्छे प्रयोगशाला प्रथाएं

चरणबद्ध रूप से कवच की स्थापना का कार्य कर रही है।

2. साबरमती लोको शेड में कवच कार्य की प्रगति

साबरमती लोको शेड में 45 हअक्कल्टउ इंजनों पर कवच स्थापित किया जाना है। इनमें से अब तक 7 इंजनों पर ट्रायल सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 38 इंजनों पर कार्य जारी है। इस कार्य हेतु 11 तकनीकी कर्मचारी तैनात हैं, जो कवच की सूक्ष्म स्थापना प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं।

3. ट्रैक सेक्शनों पर कवच इंस्टालेशन की स्थिति

अहमदाबाद – पालनपुर एवं अहमदाबाद – सामाख्याली सेक्शन (कुल 402 फ़ुट): इस रेलखंड पर कवच इंस्टालेशन हेतु निविदा जारी की जा चुकी है। कार्य के अगले दो वर्षों में पूर्ण हो जाएगा।

पालनपुर – सामाख्याली – गांधीधाम सेक्शन (लगभग 300 फ़ुट): इस खंड के लिए भी निविदा जारी की जा चुकी है तथा कार्य दो वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

जं.-गोरखपुर जं.-पनियहवा-नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी-औँड़िहार जं.-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी।

इस मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन गोंडा, गोरखपुर, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सांगली, बापूधाम मोतिहारी और

चकिया स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। उपरोक्त ट्रेन के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

कचिया स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। उपरोक्त ट्रेन के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

कचिया स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। उपरोक्त ट्रेन के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) को मंजूरी दी गई है। इसमें भारत सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी वाला 20,000 करोड़ रुपये का समुद्री निवेश कोष और ऋण की प्रभावी लागत कम करने तथा परियोजना की बैंकिंग क्षमता में सुधार हेतु 5,000 करोड़ रुपये का व्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इसके अलावा, 19,989 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) का उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन भार तक बढ़ाना, मेगा जहाज निर्माण समूहों को सहायता प्रदान करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना और जहाज रसायन परियोजनाओं के लिए बीमा सहायता

इस समग्र पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन भार की जहाज निर्माण क्षमता का विकास होने, लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। अपने आर्थिक प्रभाव के अलावा, यह पहल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री मार्गों में अनुकूलन लाकर राष्ट्रीय, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह भारत की भू-राजनीतिक

दृढ़ता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ करेगा, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक नौवहन एवं जहाज निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

भारत का एक लंबा और गौरवशाली समुद्री इतिहास रहा है, जिसमें सदियों पुराना व्यापार और समुद्री यात्रा इस उपमहाद्वीप को दुनिया से जोड़ती रही है। आज, समुद्री क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जो देश के लगभग 95 प्रतिशत व्यापार को मात्रा के हिसाब से और 70 प्रतिशत मूल्य के हिसाब से सहारा देता है। इसके मूल में जहाज निर्माण है, जिसे अक्सर "भारी इंजीनियरिंग की जननी" कहा जाता है, जो न केवल रोजगार और निवेश में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वतंत्रता और व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुकूलन को भी बढ़ावा देती है।

अहमदाबाद – गैरतपुर सेक्शन: (13.42 ^१) इस सेक्शन पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है और यह खंड अब कवच से सुसज्जित हो गया है।

कवच प्रणाली में लोको पायलट को इंजन में लगे ऑपरेशन पैनल छड-OCIP (Loco Pilot's OperAtion-cum-Indication Panel) पर ट्रेन की जानकारी जैसे कि मालगाड़ी या सवारी गाड़ी, डिब्बों की संख्या आदि भरनी होती है। इससे कवच स्वचालित रूप से ट्रेन की लंबाई और ब्रेकिंग दूरी की गणना कर लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिग्नल पार कर जाने की घटनाओं SPAD (Signal Passed At Dngger), आमने-सामने या पीछे से टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकना।

भारतीय रेलवे की यह पहल न केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से ट्रेन

भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रावधानों से जुड़े अवसरों और चिंताओं पर सेमिनार

भारत-ब्रिटेन व्यापार वार्ता में भारतीय भौगोलिक संकेतकों के लिए मजबूत संरक्षण पर जोर दिया गया

भारत ने ब्रिटेन व्यापार वार्ता में एक मजबूत और दूरदर्शी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते में संतुलित आईपी फ़्रेमवर्क स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई और पारंपरिक उत्पादकों को समर्थन देगा

(जीएनएस)। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल) के सहयोग

उपभोक्ता मामले विभाग ने रव्यापार करने में आसानी और उपभोक्ता संरक्षण - विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009३ पर गोलमेज कार्यशाला का आयोजन किया

जन विश्वास सुधार और ई-मैप पोर्टल विधिक माप विज्ञान में विश्वास, डिजिटलीकरण और व्यापार में आसानी को मजबूत करेंगे

(जीएनएस)। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'व्यापार करने में आसानी और उपभोक्ता संरक्षण - कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009' पर एक गोलमेज कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरलीकृत पंजीकरण के साथ बदलने, मरम्मतकर्ता लाइसेंस की आवश्यकता को हटाने, निमाताओं द्वारा सत्यापन की अनुमति देने, सत्यापन अवधि का विस्तार करने और जीएटीसी नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जियो-टैगिंग, जीपीएस-आधारित निरीक्षण और प्रौद्योगिकी-संचालित सत्यापन को अपनाने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कार्यशाला ने सहयोगी नीति विकास के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानूनी माप विज्ञान ढांचा पूरे भारत में निष्पक्ष और कुशल व्यापार प्रथाओं का समर्थन करते हुए उपभोक्ताओं की रक्षा करना जारी रखता है।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) की सचिव श्रीमती निधि खरे ने मुख्य भाषण दिया और कहा कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम स्पष्ट नियमों के माध्यम से व्यापार को आसान बनाने और व्यापार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के बीच

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 'सजलम भारत शिखर सम्मेलन' के अंतर्गत 'कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी' विषय पर वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और एनआरएससी हैदराबाद के राज्यों ने "कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी" पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। साथ ही लेह से लेकर तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के दूरदराज के गांवों तक के पांच जमीनी स्तर के ग्राम पंचायत और जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी (जीएनएस)।

केंद्रीय जल आयोग (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, ने 'कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी' विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन 'सुजलम भारत' शिखर सम्मेनन के हिस्से के रूप में हुआ, जिसका उद्देश्य देशभर से जमीनी अनुभव और सुझाव लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाना है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उस दृष्टि के अनुरूप है जिसमें जमीनी स्तर के विचारों को राष्ट्रीय नीति निर्माण में शामिल करने पर बल दिया गया है।

सुजलम भारत शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में, जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग, (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर), ने "कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी" विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। आज आयोजित कार्यशाला में चुनिंदा राज्यों और जमीनी स्तर के

से वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में "भारत-ब्रिटेन सीईटीए में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रावधानों से जुड़े अवसरों और चिंताओं" पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में नीति निमाताओं, क्षेत्र विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रावधानों से संबंधित अवसरों और चिंताओं पर विचार-विमर्श किया।

सेमिनार में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि बौद्धिक संपदा अधिकार अध्याय नवाचार को बढ़ावा देने और पहुंच सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाता है। इस बात पर जोर दिया गया कि ये प्रावधान भारत के आईपी ढांचे का आधुनिकीकरण करते हुए जन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करते हैं। प्रतिभागियों ने दोहराया कि स्वेच्छिक लाइसेंसिंग उद्योग जगत में पसंदीदा प्रथा बनी हुई

उपभोक्ता मामले विभाग ने रव्यापार करने में आसानी और उपभोक्ता संरक्षण - विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009३ पर गोलमेज कार्यशाला का आयोजन किया

संतुलन स्थापित करता है। श्रीमती खरे ने ई-मैप पोर्टल, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, तौल और माप उपकरणों के लिए नए नियम,



ओआईएमएल प्रमाणन और समय प्रसार परियोजना जैसी प्रमुख पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने विधिक माप विज्ञान संबंधी प्रश्नों के लिए प्रत्येक मंगलवार को शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक वन-स्टॉप सुविधा की हेल्पडेस्क (जन सुनवाई) शुरू की है। डीओसीए सचिव ने बताया कि विभाग ने ई1 और ई2 श्रेणी के बाटों की आवश्यकताओं को समेकित कर दिया है और राज्यों को लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत वाले 519 ई2 श्रेणी के बाट और 297 ई1 श्रेणी के बाट उपलब्ध कराए जाने हैं।

जन विश्वास 1.0 और 2.0 के तहत सुधारों का उल्लेख करते हुए, श्रीमती खरे ने कहा कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 में अपराधमुक्त धाराओं और सुधार नोटिस लागू करने के प्रस्ताव से बाधाएं दूर होंगी, व्यवसायों का विकास होगा और नागरिकों और

है, जबकि अनिवार्य लाइसेंसिंग और जन स्वास्थ्य से संबंधित लचीलेपन, जैसा कि दोहा घोषणापत्र में निहित है, पूरी तरह से संरक्षित हैं। पेटेंट प्रक्रियाओं के सामंजस्य पर चिंताओं का समाधान किया गया, और विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रियात्मक सुधार हैं जो किसी भी तरह से भारत की नियामक स्वायत्तता को प्रभावित नहीं करते। भौगोलिक संकेत (जीआई) अवसर के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरे, समझौते के प्रावधानों से ब्रिटिश बाजार में भारतीय भौगोलिक संकेतों की मजबूत सुरक्षा संभव हुई - जो निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक ब्रांडिंग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योग प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि इससे स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई और पारंपरिक उत्पादकों, सभी को समान रूप से लाभ होगा।

पैनल ने समझौते से जुड़ी कई

उपभोक्ता संरक्षण - विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009३ पर गोलमेज कार्यशाला का आयोजन किया

प्रस्तावित अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और ई-मैप पोर्टल के विकास पर एक प्रस्तुति दी, जो प्रवर्तन सहित कानूनी माप विज्ञान के सभी कार्यों को एकीकृत करेगा, एक एकीकृत डेटाबेस बनाएगा, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाएगा और अधिकारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा।

उद्योग संघों ने उद्योगों को एमआरपी में संशोधन करने में छूट देने और जीएसटी की कम दरों का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जारी की गई सलाह की सराहना की। उन्होंने अधिनियम और नियमों में संशोधन, उपकरणों के सत्यापन की हितधारक सहयोग से विश्वास और समय-सीमा में संशोधन, निमाताओं/डीलरों और मरम्मत करने वालों के लिए लाइसेंसिंग को

युक्तिसंगत बनाने और अधिनियम के तहत फेसलेस और स्व-सत्यापन की सहआत का सुझाव दिया। वीसीओ ने बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले उल्लंघनों के संख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर सुनिश्चित करता है। जन विश्वास सुधारों का हवाला देते हुए—2023 में सात प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करना, कारावास के स्थान पर दंड लागू करना, और 2025 में सुधार नोटिस लागू करना—उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन विश्वास का निर्माण करेगा और एक निष्पक्ष व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देगा।

डीओसीए के संयुक्त सचिव श्री अनुपम मिश्रा ने जन विश्वास 2.0 के तहत गैर-अपराधीकरण के लिए

भ्रातियों को दूर किया और स्पष्ट किया कि आईपीआर चैप्टर भारत की नीतिगत संभावनाओं को सीमित नहीं करता। बल्कि, यह भारत की अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप नियम बनाने की क्षमता को मजबूत करता है। यह भी रेखांकित किया गया कि यह अध्याय भारत के मौजूदा कानूनी ढांचे को दर्शाता है और वैश्विक साझेदारों तथा निवेशकों को एक मजबूत और दूरदर्शी बौद्धिक संपदा व्यवस्था के प्रति देश की प्रतिबद्धता का सकारात्मक संकेत देता है।

सेमिनार का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि भारत-ब्रिटेन सीईटीए का आईपीआर चैप्टर भावी व्यापार वाताओं के लिए एक प्रारूप प्रदान करता है - जिसमें लचीलेपन के साथ विनियामक कठोरता का संयोजन, पहुंच की सुरक्षा करते हुए नवाचार का समर्थन तथा उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करना शामिल है।

हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें हिन्दी भाषा जनभाषा के रूप में विकसित हो - श्री जी किशन रेड्डी, माननीय खान मंत्री जी।

खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

(जीएनएस)।

खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने की। बैठक में माननीय सांसदगण श्री भर्तृहरि महताब (सांसद, लोकसभा), श्री भोजराज नाग (सांसद, लोकसभा), श्री कालीचरण सिंह (सांसद, लोकसभा), श्री सुजीत कुमार (सांसद, राज्यसभा), श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (सांसद, राज्यसभा) सहित समिति के अन्य सदस्यगण, श्री पीयूष गोयल, सचिव (खान) तथा खान

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की उपस्थिति में जेप्टो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

समझौता ज्ञापन से युवा नौकरी चाहने वालों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से नए अवसर खुलेंगे

समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान जेप्टो 10,000 नौकरियों के अवसर प्रदान करेगा, जिससे शहरी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

एनसीएस पोर्टल पर अब तक लगभग 7.5 करोड़ रिक्रियां उपलब्ध ध कराई गई हैं

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर रोजगार के अवसरों के

मंत्रालय के उच्च अधिकारीगण

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि तथा

माननीय खान मंत्री ने अपने

संबोधन में कहा कि हिंदी केवल



मंत्रालय द्वारा नामित समिति के

माननीय सदस्य उपस्थित रहे।

संचार का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी

सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय

साथ-साथ युवाओं की रोजगार क्षमता

बढ़ाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और जेप्टो के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर

डॉ. मांडविया ने अपने संबोधन में कहा, "राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच एक अनूठे सेतु के रूप में उभरा है। अपनी



आज नई दिल्ि में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडविया की उपस्थिति में

स्थापना के बाद से 52 लाख से अधिक पंजीकृत नियोक्ताओं और लगभग 7.5 करोड़ रिक्रियां के साथ एनसीएस ने स्वयं को सभी रोजगार-संबंधी सेवाओं

वेवएक्स ने मीडिया, मनोरंजन और एवीजीसी-एक्सआर सेक्टर के स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए सात नए इनक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की घोषणा की

आईआईएमसी (दिल्ली, जम्मू, ढ़ैकनाल, कोट्टायम, अमरावती), एफटीआईआई-पुणे और एसआरएफटीआई कोलकाता में स्थापित होने वाले ये नए केंद्र फिल्म, गेमिंग और एक्सआर स्टार्टअप्स के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे

आईआईसीटी, एफटीआईआई, एसआरएफटीआई और अन्य साझेदार इनक्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप्स को फिल्म निर्माण, गेम डेवलपमेंट, संपादन और परीक्षण के लिए उन्नत सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी

(जीएनएस)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेब्स पहल के अंतर्गत समर्पित स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म- 'वेवएक्स' ने पूरे भारत में सात नए इनक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। ये सात केंद्र भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) मुंबई के अलावा होंगे। यह पहली बार है जब एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कम्पिक्स) और एक्सआर (एक्सटेंडेड रियलिटी) क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से एक समर्पित

एक्सेलेरेटर-सह-इनक्यूबेटर कार्यक्रम शुरू किया गया है।

सात नए केंद्र:



नए घोषित ये केंद्र निम्नलिखित संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे: भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली आईआईएमसी, जम्मू आईआईएमसी, ढ़ैकनाल, ओडिशा आईआईएमसी, कोट्टायम, केरल आईआईएमसी, अमरावती, महाराष्ट्र

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे, महाराष्ट्र

सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता, पश्चिम बंगाल

इन इनक्यूबेशन नेटवर्कों के शुभारंभ के साथ, स्टार्टअप्स को रियलिटी) क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से एक समर्पित

इनक्यूबेटरों के माध्यम से फिल्म निर्माण, गेम डेवलपमेंट, संपादन और परीक्षण के लिए उन्नत सुविधाओं तक

पहुंच प्राप्त होगी। मुंबई स्थित प्रमुख आईआईसीटी इनक्यूबेटर, 8के रेड रैटर विस्टा विजन कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 4के एचडीआर प्रीयू थिएटर, उच्च-प्रदर्शन वाले एलियनवेयर वर्कस्टेशन, एलईडी दीवारों वाला एक अत्याधुनिक वर्चुअल प्रोडक्शन स्ट्रेज, फोटोग्रामेट्री सिस्टम, पेशेवर साउंड और कलर-मिक्स थिएटर, 4के एचडीआर एडिट सूट, वीआर टेरिस्टिंग किट और नवीनतम गेमिंग कंसोल जैसे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सुसज्जित है।

ये सुविधाएं स्टार्टअप को फिल्म, गेमिंग और इमर्सिव मीडिया में वैश्विक मानकों के अनुरूप सामग्री डिजाइन, विकसित और सत्यापित करने में कारगर बनाती हैं। वेवएक्स के अंतर्गत

कैबिनेट ने 2277.397 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डीएसआईआर योजना 'क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास' को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पंद्रहवें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 2277.397 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 'क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास' पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डीएसआईआर/सीएसआईआर) योजना को मंजूरी दे दी है।

इस योजना में सीएसआईआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और देश भर के सभी अनुसंधान परियोजनाओं में सीएसआईआर/सीएसआईआर) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में सीएसआईआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और देश भर के सभी अनुसंधान परियोजनाओं में सीएसआईआर/सीएसआईआर) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में सीएसआईआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और देश भर के सभी अनुसंधान परियोजनाओं में सीएसआईआर/सीएसआईआर) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में सीएसआईआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और देश भर के सभी अनुसंधान परियोजनाओं में सीएसआईआर/सीएसआईआर) योजना को मंजूरी दे दी है।

प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में, यह योजना विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान (एसटीईएमएस) के विकास को बढ़ावा देगी।

क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास योजना, प्रति दस लाख जनसंख्या पर शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण और उत्पन्न-गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों के भंडार का विस्तार करके अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है।

पिछले दशक के दौरान भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के लिए किए गए समन्वित प्रयासों से, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

(डब्ल्यूआईपीओ) की रैंकिंग के अनुसार, भारत ने 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में अपनी स्थिति सुधारकर 39वीं रैंक प्राप्त कर ली है, जो भारत की प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन में निकट भविष्य में और भी बेहतर होगी। सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास को दिए गए सहयोग (८) परिणामस्वरूप, एमएसएफ, यूएसए के आंकड़ों के अनुसार, भारत अब विश्व में शीर्ष तीन में शामिल है। डीएसआईआर की योजना हजारों शोधार्थियों और वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान कर रही है, जिनके परिणामों ने भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अनुमोदन ने सीएसआईआर की अम्ब्रेला योजना कार्यान्वयन के माध्यम से सीएसआईआर की भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को दी गई 84 वर्षों की सेवा के लिए

एकता का सेतु है। उन्होंने मंत्रालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के पूर्ण अनुपालन और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। माननीय खान मंत्री जी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें हिन्दी भाषा जनभाषा के रूप में विकसित हो और सरकारी नीतियों और योजनाओं से आम जन लाभान्वित हों।

बैठक में समिति सांसदों और सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए जिसको लेकर मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। सभी आधिकारिक पत्राचार, नोटशीट्स, ई-मेल और डिजिटल

के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में स्थापित किया है।"

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "निकट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अन्य विश्व स्तरीय डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एनसीएस पोर्टल को मजबूत करने से नौकरी चाहने वालों को उनकी स्थान आवश्यकताओं और संबंधित योग्यताओं के अनुरूप अवसरों की पहचान करने में मदद मिलेगी।"

मंत्रालय और जेप्टो के बीच सहयोग का स्वागत करते हुए डॉ. मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोलेगी, साथ ही जेप्टो को मानव संसाधन के उपयुक्त प्रतिभा पूल से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी।